



Reading Material on :- **Bail**

Workshop Dated 2/2/2026

District Court Durg (C.G.)

Prepared By-

Smt. Shiksha Meshram

ADPO, Durg (C.G.)

BAIL

WORKSHOP DATED 02.02.2026

DISTRICT COURT DURG

संविधान का अनुच्छेद 21 यह कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन यापन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

यही कारण है कि कोर्ट जमानत देते समय यह देखती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न हो बशर्ते वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करे या भाग न जाए।

जमानत मिलना केवल जेल से बाहर आना नहीं है, बल्कि यह कानून और कोर्ट द्वारा दी गई जिम्मेदारी है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) जमानत प्रावधानों के संबंध में महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं, जैसे जमानत, जमानत बॉन्ड, बॉन्ड की परिभाषाएँ शामिल हैं। इसके अलावा विचाराधीन कैदी की हिरासत की अधिकतम अवधि और अग्रिम जमानत के प्रावधान में भी बदलाव किए गए हैं।

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (Indian Criminal Procedure Code) में जमानत को परिभाषित नहीं किया गया, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा (2) का खंड (B) में जमानत का अर्थ है कि किसी अपराध के आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति को किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा बॉन्ड, जमानत बॉन्ड के निष्पादन पर लगाई गई कुछ शर्तों पर कानून की हिरासत से रिहा करना है।

विचाराधीन कैदियों को लेकर किये गये बदलाव – धारा 436 (A) भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (Indian Criminal Procedure Code) अपराधिक संशोधन अधिनियम 2005 के तहत शामिल किया गया है कि जहाँ एक विचाराधीन अपराधी को अपराध के लिये निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की अवधि के लिये हिरासत में रखा गया है (मृत्यु से दंडनीय नहीं), उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जाएगा। यह प्रावधान विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में चल रहे आरोपी के निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई के अधिकार के मान्यता के रूप में जोड़ा गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 जो धारा 436 (A) का प्रतिरूप है, में विचाराधीन कैदियों को जमानत देने के प्रावधान में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाये गये हैं जैसे – पहली बार के अपराधी यदि निर्धारित सजा के एक तिहाई तक की अवधि विचाराधीन कैदी के रूप में बीता ली है तो उसे जमानत दिया जाये।

अग्रिम जमानत के लिये – 18 वर्ष से कम उम्र की सभी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में पहला प्रावधान यह कहता है कि यदि अभियुक्त ऐसा अपराध करने का आरोपी है जो सत्र न्यायालय में विचारणीय है जिसके लिये आजीवन कारावास का प्रावधान है तो न्यायालय अभियोजन पक्ष को सुने बिना जमानत आवेदन का निराकरण नहीं करेगी, इससे पहले भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (Indian Criminal Procedure Code) में धारा 439 में ऐसा प्रावधान था लेकिन इसे और भी स्पष्टता के साथ शामिल किया गया है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि गंभीर अपराधों में बिना अभियोजन पक्ष की सुनी गई बात के जमानत नहीं दी जाये। धारा 65 और धारा 70 (2) के मामलों में लोक अभियोजक को जमानत आवेदन की

सूचना 15 दिनों के भीतर देना अनिवार्य है। यह प्रावधान यौन अपराध की गंभीरता और पीड़ित के अधिकारों की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

धारा 483 (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) पीड़ित या उसके प्रतिनिधी की उपस्थिति यदि धारा 65 या धारा 70 (2) के मामलों में सूचना देने के साथ यह भी अनिवार्य है कि पीड़ित या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति जमानत की सुनवाई के समय न्यायालय में उपस्थित हो इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ित पक्ष की भी आवाज न्यायालय में सुनी जाये और आरोपी के जमानत आवेदन पर विचार करने के पहले पीड़ित पक्ष की भावनाओं और स्थिति को ध्यान में रखा जाये।

धारा 483 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) जमानत रद्द कर पुनः हिरासत में लेने का आदेश है। यह धारा उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय को यह शक्ति देती है कि ऐसे किसी भी अभियुक्त को जिसे इस अध्याय के अंतर्गत जमानत दी गई है फिर से गिरफ्तार करने और हिरासत में भेजने का निर्देश देती है।

इस प्रावधान का महत्व इस लिये है क्योंकि यह जमानत का दुरुपयोग रोकने के लिये न्यायालय को प्रभावी उपाय प्रदान करता है कि यदि कोई अभियुक्त जमानत पर रहते हुए गवाहों को धमकाता है या जॉच में बाधा डालता है तो न्यायालय उसे फिर से हिरासत में भेज सकता है। धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) गैर जमानती अपराधों में जमानत से संबंधित है। धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) यह कहती है कि जब किसी आरोपी को जमानत दी जाती है तो उसे यह बंधन देना होता है कि यदि उच्चतर न्यायालय में कोई अपील या याचिका चले तो वह वहाँ उपस्थित होगा। धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) अग्रिम जमानत से संबंधित है और धारा 483 में इसका विस्तार देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह दोहराया है कि गंभीर अपराधों में जमानत एक सामान्य अधिकार नहीं है बल्कि एक न्यायिक विवेक का मामला है।

कल्याण चंद्र सरकार बनाम राज्य पश्चिम बंगाल 2004 इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत देते समय अदालत को अपराध की प्रकृति, साक्ष्यों की गंभीरता, आरोपी की सामाजिक स्थिति, पीड़ित की स्थिति और न्याय में बाधा पहुँचाने की संभावना जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए।

Stat of Rajasthan Vs Balchand Alies Baliya 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम है, जेल अपवाद, लेकिन यह नियम तभी लागू होगा जब अपराध सामान्य प्रकृति का है, गंभीर अपराधों में यह कहना उतना सटीक नहीं रहता।

धारा 485, न्यायालय को यह शक्ति देती है कि e Bail दे सकते हैं, शर्तें लगा सकते हैं, आवश्यक हो तो आरोपी को पुनः हिरासत में भी ले सकते हैं। धारा में यह सुनिश्चित किया गया है कि गंभीर यौन अपराधों में अभियोजन पक्ष और पीड़ित को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिले।

यह एक न्यायिक विवेक, संतुलन और संवेदनशीलता का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली की जड़ों को मजबूत करता है।

SC, ST Act में देखें तो SC ने इस बात पर जोर दिया कि SC, ST अधिनियम की धारा 18 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 438 के आवेदन को बाहर करती है जो अग्रिम जमानत की अनुमति देती है। किरण बनाम राजकुमार, जीवराज जैन एवं अन्य में सुप्रीम न्यायालय ने पीड़ितों की धमकियों से बचाने और प्रभावी अभियोजन को सुनिश्चित करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया है।

मध्यप्रदेश राज्य बनाम राजकृष्ण बसोठिया (1995)

विलास पंडुरंग पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2012 और पृथ्वीराज चौहान बनाम भारत संघ (2020) जैसे पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि अधिनियम के अंतर्गत अपराध एक विशिष्ट श्रेणी बनाते हैं जो प्रणालीगत अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव से जुड़े हैं, यह प्रतिबंध संवैधानिक रूप से वैध है और संविधान के अनुच्छेद 14 धारा 21 का उल्लंघन नहीं करता है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय जमानत के चरण में लघु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। उन्हें केवल यह जाँचने की आवश्यकता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।

X बनाम उत्तरप्रदेश राज्य 2026 INJ (44)

मे सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा की गई जमानत रद्द कर दी।

Supreme Court ने कहा कि –

जावको जैन मामलों में जमानत सामान्य नियम नहीं है। यदि अपराध गंभीर/जघन्य है तो जमानत के समय बहुत सरल दृष्टिकोण अपनाना होगा।

Supreme Court ने यह कहा कि –

- जमानत यांत्रिक तरीके से नहीं दी जा सकती।

Supreme Court ने कहा कि –

सिर्फ यह कहकर जमानत नहीं दी जा सकती कि चार्ज शीट अविलंब हो गई है या आरोपी जेल में काफी समय से कोर्ट को अपराध की गंभीरता प्रथम दृष्टया साक्ष्य, संवेदनशीलता का ध्यान रखना होगा।

- पीड़ित की उम्र का फैसला जमानत करने पर नहीं होगा।

State of U.P. बनाम अनुरुद्ध 2026 INS (47)

- पीड़ित नाबालिग है या नहीं इसका अंतिम निर्णय ट्रायल के दौरान होगा।
- जमानत सुनवाई के समय कोर्ट को इस पर अंतिम फैसला नहीं देना चाहिए।

नीरू यादव बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल जेल में लंबा समय बीताना जमानत का आधार नहीं हो सकता। जब अपराध समाज और पीड़ित के लिये गंभीर खतरा हो।

नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वर्सेस मोहित अग्रवाल 2022 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 37 की दोहरी शर्तें पूरी हुए बिना जमानत देना अवैध है और यह भी कहा कि लंबी हिरासत भी स्वतः जमानत का आधार नहीं है।

गिरफ्तारी संबंधी महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत –

अर्नेस कुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार 2014 – के निर्णय में दिये गये कानूनी प्रावधान एवं आवश्यक दिशा निर्देश –

- न्यायालय ने कहा कि सिर्फ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से गिरफ्तारी अपने आप नहीं होनी चाहिए।
- पुलिस को पहले तय करना होगा कि गिरफ्तारी वाकई जरूरी है या नहीं।

धारा 41CR.P.C./35 B.N.S.S. का पालन अनिवार्य –

- पुलिस तभी गिरफ्तारी कर सकती है जब आरोपी के भागने की आशंका हो, सबूत मिटाने की संभावना हो, गवाहों को डराने की आशंका हो या अपराध दुबारा करने का खतरा हो।

कारण लिखित में दर्ज करना होगा – अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो कारण लिखित में बताने होंगे अगर गिरफ्तार नहीं करती है तब भी उसका कारण दर्ज करना होगा।

न्यायालय की जिम्मेदारी – न्यायालय बिना सोचे समझे रिमांड नहीं देगी। यह देखना होगा कि पुलिस ने धारा 41 का पालन किया या नहीं।

नोटिस ऑफ अपिरियेंस – धारा 41 (ए) CR.P.C. जहाँ गिरफ्तारी जरूरी नहीं है वहाँ पुलिस सीधे गिरफ्तार करने के बजाय नोटिस भेजेगी। अगर आरोपी सहयोग करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जायेगा और सहयोग नहीं करता है तो कारण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है।

किसी आरोपी को गिरफ्तार न करने का निर्णय – मामले की शुरुआत की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा और जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित रूप से दर्ज किये जाने वाले कारणों से बढ़ाया जा सकेगा। वर्ष 2009 में धारा 41 (ए) को दंड प्रक्रिया संहिता में जोड़ा गया था जो 2 नवंबर 2010 संशोधित होकर सीआरपीसी में जोड़ा गया था। जिसमें पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने व न करने के कारण को दर्ज करने और उपरोक्तानुसार गिरफ्तारी करने या न करने का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2014 में उपरोक्त निर्णय में उक्त प्रावधान का विस्तार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यक दिशा निर्देश दिये थे। सीआरपीसी 41 (ए) (1) पुलिस अधिकारी उन सभी मामलों में जहाँ उप धारा 1 के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा जिसके खिलाफ उचित शिकायत की गई है। उचित संदेह है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है कि वह उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर उपस्थित हो जैसा कि नोटिस में निर्दिष्ट किया गया है।

सीआरपीपी 41 ए 2 जहाँ किसी व्यक्ति को ऐसा नोटिस जारी किया जाता है तो उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह नोटिस की शर्तों का पालन करे।

धारा 41 (ए) (4) यदि ऐसा व्यक्ति किसी भी समय नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या अपनी पहचान बताने को तैयार नहीं रहता है तो पुलिस अधिकारी सक्षम न्यायालय के आदेशों के अधीन रहते हुए उसे नोटिस में उल्लेखित अपराध के लिये गिरफ्तार कर सकता है। पुलिस अधीक्षक से कम रैंक के अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा, ऐसे अपराध के मामलों में जिनमें तीन वर्ष से कम कारावास की सजा हो और ऐसा व्यक्ति दुर्बल हो या साठ वर्ष से अधिक आयु का हो।

बी0एन0एस0एस0 की प्रारंभिक 06 उप धाराएँ 35 (1) से 35 (6) सी0आर0पी0सी0 की धारा 41 व 41 (ए) का पूर्ण प्रतिरूप है।

पुलिस अधिकारी यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्णय लेता है तब वह विधिवत भरी हुई चेक लिस्ट अग्रेषित करेगा और गिरफ्तारी को आवश्यक बनाने वाले कारणों व सामग्रीयों को प्रस्तुत करेगा जब अभियुक्त को आगे की हिरासत के लिये मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट अभियुक्त की हिरासत अधिकृत करते समय पुलिस अधिकारी द्वारा उपरोक्त तरीके से प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करेगा और केवल अपनी संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही हिरासत अधिकृत करेगा। निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित पुलिस अधिकारी पर विभागीय जाँच की जायेगी एवं क्षेत्रीय अधिकार वाले उच्च न्यायालय में अवमानना का मुकदमा भी चलाया जायेगा। वर्तमान समय में पुलिस अधिकारी धारा 41एसीसी के तहत नोटिस के आधार पर आरोप पत्र दाखिल कर रहे हैं, वे भूल जाते हैं कि उक्त नोटिस केवल एक नोटिस है कोई जमानत नहीं है।

सतयेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई 2022 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी जेलें दोषियों से नहीं अंडर ट्रॉयल कैदियों से भरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त निर्णय के माध्यम से जमानत प्रक्रिया के संबंध में नई गाईड लाईस जारी की और कहा कि जमानत याचिकाओं का निपटारा जल्द से जल्द (दो सप्ताह) होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी तभी हो जब आरोपी भाग सकता है, सबूत मिटा सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को जमानत को लेकर स्पष्ट नीति एवं नियम बनाने को निर्देशित किया। यह पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सरकार को बिल पॉलिसी बनाने को कहा। उक्त फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेस कुमार के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करने को कहा, ये निर्देश केवल राज्य पुलिस नहीं बल्कि सीबीआई एवं ईडी जैसे केंद्रीय एजेंसियों पर भी लागू है।

मुख्य निर्देश :- सुप्रीम कोर्ट ने अपराधों की चार श्रेणियाँ तैयार कि -

ए श्रेणी - ऐसे अपराध जिनकी सजा 7 साल तक है और गिरफ्तारी जरूरी नहीं।

बी श्रेणी - आर्थिक अपराध

सी श्रेणी - विशेष कानून - एनडीपीएस, पीएमएलए

डी श्रेणी - ऐसे मामले जहाँ आरोपी उद्घोषित आरोपी हो।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत खारिज प्रकरण :-

- **उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सिंह सेंगर के विरुद्ध जमानत आवेदन पर विचार करते हुए 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि गंभीर प्रकरण में दोषी व्यक्ति को जमानत देना तुरंत मंजूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि गंभीर अपराधों से बलात्कार, यूएपीए एवं बाल तस्करी आदि में जमानत देते या नहीं देते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए केवल समानता के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती बल्कि आरोपी की भूमिका, अपराध की प्रकृति और उपलब्ध साक्ष्य देखे जाने चाहिए।**
- **अन्ना उमेन भालेराव विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र – 12 सितंबर 2025 के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत को रिजेक्ट करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोपो के लिये हिरासत आवश्यक है ताकि जॉच सुचारु रूप से हो सके। यह निर्णय बताता है कि कभी-कभी जमानत सिर्फ इसलिए नहीं दी जाती की जॉच जारी हो।**
- **UAPA Case – सरजील इमाम और उमर खालिद के जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए 5 जनवरी 2026 को दिल्ली दंगे 2020 के आरोपी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आतंक/उग्रवाद के आरोपों में बेल पर कड़ा रुख अपनाते हुए जमानत याचिका खारिज की।**
- **हमने सीखा जमानत कोई स्थायी अधिकार नहीं है अगर आरोपी शर्तों का पालन नहीं करता है तो कोर्ट बीएनएसएस की धारा 483 (3) के तहत जमानत रद्द कर सकता है। अगर आरोपी गवाहों को डराता है, प्रभावित करता है, फरार हो जाता है या आरोपी जमानत पर रिहा होकर दुबारा अपराध करता है।**
 - **State of Rajasthan Vs Balchand Balia 1977 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी का फरार होने की आशंका हो और सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा हो तो जमानत रोकी जा सकती है। बिल रिजेक्ट करने का आधार यहि से विकसित हुआ।**
 - **State of Bihar Vs Rajballav Prasad (2017) -**
 - **में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ित की सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई की पवित्रता सर्वोपरि है।**
 - **जेलों की संख्या – 1330.**
 - **कैदियों की संख्या – 05,73,200**
 - **क्षमता से 131.4 प्रतिशत अधिक**
 - **अंडर ट्रायल 75 प्रतिशत से अधिक**

अरनेश कुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार (2014)

धारा 35 का सार —

- सात साल तक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी से पहले नोटिस देना अनिवार्य।
- कारण लिखे बिना गिरफ्तारी नहीं।
- मजिस्ट्रेट को भी गिरफ्तारी का कारण देखना होगा।

पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है —

- पुलिस को कारण बताना होगा कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी?
- आरोपी ने धारा 41 A नोटिस का पालन नहीं किया तब पुलिस गिरफ्तार कर सकती है।
- गिरफ्तारी का कारण बताना होगा जो चेक लिस्ट के माध्यम से भरा जायेगा।
- न्यायालय को यह देखना होगा कि चेक लिस्ट सही रूप से भरी गई है या नहीं।
- यदि चेक लिस्ट नहीं भरी गई है तो गिरफ्तारी अवैध मानी जायेगी।
- आरोपी को बेल मिल सकती है एवं पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जाँच तथा न्यायालय द्वारा प्रक्रिया के पालन की अनदेखी किये जाने पर न्यायालय की अवमानना मानी जायेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश के केस में यह नहीं कहा है कि गिरफ्तारी बिलकुल हो सकती, लेकिन मनमानी गिरफ्तारी नहीं हो सकती।

पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं करने की प्रक्रिया —

- 41 A का नोटिस दो सप्ताह के भीतर आरोपी को देना होगा।
- न्यायालय को भी सूचना दो सप्ताह के भीतर देना है कि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
- पुलिस अधीक्षक दो सप्ताह से अधिक की अवधि को बढ़ा सकते हैं।
- धारा 35 (3) में पुलिस अधिकारी आरोपी को उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर उपसंजात होने के लिए निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा।
- नोटिस में केवल थाने में उपस्थित होने को ही नहीं बल्कि विवेचना हेतु अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होने का निर्देश दिया जायेगा।

अरनेश के जजमेंट के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि गिरफ्तारी अपराध की प्रकृति पर नहीं बल्कि गिरफ्तारी की आवश्यकता पर निर्भर करती है।

(श्रीमती शिक्षा मेश्राम)
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी
जिला अभियोजन निदेशालय
जिला — दुर्ग, (छ0ग0)।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):

यह रिसर्च पेपर लेखक के व्यक्तिगत अध्ययन एवं विश्लेषण पर आधारित है तथा इसमें व्यक्त विचार लेखक के निजी हैं। यद्यपि इसे सटीक एवं अद्यतन रखने का प्रयास किया गया है, तथापि इसमें त्रुटि या सुधार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसे पूर्णतः प्रामाणिक अथवा विधिक सलाह के रूप में न माना जाए। किसी भी विधिक निर्णय से पूर्व संबंधित कानूनों एवं विशेषज्ञ परामर्श का संदर्भ लिया जाना अपेक्षित है।